

नम्बर व
अहकाम
की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निराल संख्या 059/2013

निर्णय दिनांक :- 24-12-202

उनवानी दावा :

सुवालाल पुत्र श्री गोकुल जाति कीर उम्र 55 वर्ष निवासी अलेक्जेंडरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

- वादीगण -

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार जी, देवली तहसील देवली जिला-टोंक

- प्रतिवादीगण -

उपस्थिति :-

श्री रामलाल कटारिया
अधिवक्ता वादी

पैरोकार सरकार

दावा उद्घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी भूमिहीन किसान है। वादी के नाम से काश्त करने पर एवं परिवार का जीविका उपार्जन कि लिए कोई साधन नहीं है। वादी की कब्जा-काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 83 रकगा 0.37 है0 वाके ग्राम अलेक्जेंडरपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त कृषि भूमि बंजड़ थी जिसको अपने पिता के जीवनकाल में लगभग 40 वर्षों पूर्व काफी रूपया खर्च कर तथा भूमि की लेवलिंग कर बालिग-काश्त बनाया। तब से लेकर आज-तक वादी के ला व उसकी मृत्यु के बाद वादी का कब्जा-काश्त बिना किसी बाधा के निर्विघ्न एवं निरन्तर उक्त भूमि पर चला आ रहा है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में पी-14 संवत 2047 आज तक दर्ज चला आ रहा है। संवत 2055 से उक्त आराजीयात पर काश्त करते हुए वादी ने सरकार को लगान व पेनल्टियां अदा करता आ रहा है। जबकि वादी का करीब 40 वर्षों से उक्त भूमि कब्जा-काश्त होने पर आज भी उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक सरकारी भूमि अंकित है। वादी भूमिहीन काश्तकार है। वादी अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण उक्त भूमि की उपज से करता चला आ रहा है। वादी के पास परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अन्य कोई जमीन नहीं है। वादी ने प्रशासन गांव के संग अभियान मे उक्त कब्जे-काश्त की भूमि को अपनी खातेदारी मे दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिये। जबकि वादी उक्त भूमि पर लगातार पिछले 40 वर्षों से काबिज- काश्त है। इस कारण वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी उक्त भूमि को अपनी खातेदारी में लगवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी नं. 2 अपने प्रभाव का बेजा इस्तेमाल कर वादी को उसकी उक्त कब्जे-काश्त की भूमि के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है तथा वादी को बेदखल कर अन्य को आवंटित करना चाहता है तथा गांव के कई प्रभावशाली आये दिन वादी को उक्त भूमि के कब्जे-काश्त उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण वाद वर्णित उक्त भूमि को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज कर वादी को उक्त

Di. 24

भूमि का खातेदार-काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायहित में प्रतिवादी नं. 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा-हमेशा के लिए पाबंद किया जावे कि वह स्वयं जरिए अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारियों के वादी को वाद वर्णित भूमि के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादी को उक्त भूमि से बेदखल नही करे, वादी की उक्त भूमि को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे एवं पाबंद रहे। यदि प्रतिवादीगण नं. 2 को उक्तानुसार पाबंद नहीं किया गया तो वादी को जबरन बेदखल कर देंगे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से परोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वादपत्र का चरण संख्या 1 स्वीकार नहीं है। वादपत्र का चरण संख्या 2 स्वीकार नहीं है। वादपत्र का चरण संख्या 3 स्वीकार नहीं है। वादपत्र का चरण संख्या 4 स्वीकार नहीं है। वादपत्र का चरण संख्या 5 व 6 स्वीकार नहीं है। वादपत्र का चरण संख्या 7 लगायत 10 न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से जवाब अपेक्षित नहीं है। वादपत्र में वर्णित भूमि ख. नं. 83 बरूह रिकार्ड पटवार सिवायचक सरकार की भूमि है जिस पर वादी द्वारा आवंटन/नियमन की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। वादी धारा 88 के तहत खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है वाद पत्र खारीज किये जाने योग्य है। प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर सुनवाई जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:- प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत 2064-67, प्रदर्श-2 व 3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श- 2 से 5 पी-14 सम्वत 2047, 2049, 2060, 2059 प्रदर्श-6 ता 10 खसरा परिवर्तनशील निर्धारण सम्वत 2049, 2053, 2054, 2055, 2057 प्रदर्श-11 ता 14 खसरा परिवर्तन निर्धारण सम्वत 2061, 2063, 2065, 2062 प्रदर्श-15 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-16 ता 18 लगान रशीदे पेश किये है। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू-1 वादी सुवालाल पुत्र श्री गोकुल जाति कीर निवासी अलेक्जेंडरपुरा तहसील देवली का पेश किया है। परोकार सरकार द्वारा जिरह नही करने से वादी जिरह बन्द की जाकर पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

परोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के पूर्वज व वादी खसरा नम्बर 83 रकबा 0.37 है0 पर 40 वर्षों से अधिक काश्त करता आ रहा है। आज भी वादी का कब्जा काश्त है और नियमानुसार वाद पेनल्टी अदा करता आ रहा है। इसके लिए वादी ने रिकॉर्ड पेश किया है। तहसीलदार देवली ने अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। इसके लिए उच्च न्यायालयो ने कई बार इस सम्बन्ध में एडवर्ज पजेशन के आधार पर खातेदारी देने हेतु निर्देशित किया है। वादी व वादी के परिवार का भरण पोषण इसी आराजीयात से होता है, वादी के पास इसके अलावा कोई आराजी नहीं है। 40 वर्षों से अधिक समय तक कब्जा काश्त होने से वादी

A.2

खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी का दावा डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को ही बहस मानने हेतु प्रार्थना की।

तनकीवार निर्णय:—

तनकी नं. 1:— आया वादी विवादित आराजी ख. नं. 83 रकबा 0.37 है 0 , वाके ग्रम अलेकजेन्डरपुरा तहसील देवली आराजी कदीमी 40 वर्षों से निर्बाध कब्ज काशत चले आ रहे हैं और अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने के हकदार हैं ?

—वादी—

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। इसके लिए वादी ने प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत 2064-67, प्रदर्श- 2 से 5 पी-14 सम्वत 2047, 2049, 2060, 2059 प्रदर्श-6 ता 10 खसरा परिवर्तनशील निर्धारण सम्वत 2049 ,2053, 2054, 2055, 2057 प्रदर्श-11 ता 14 खसरा परिवर्तन निर्धारण सम्वत 2061, 2063, 2065, 2062 प्रदर्श-15 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-16 ता 18 लगान रशीदे पेश किये हैं। विगत पी-14 की नकलो को प्रदर्शित करवाने से, राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की मूल भावना के तहत खातेदारी अधिकार तय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। साथ ही वादी द्वारा राजकीय अधिकारियों को पक्षकारान बनाने से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना होता है जो कि वादी द्वारा नहीं दिया गया है। अतः वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध में दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण तनकी नं. 1 को साबित करने में असफल रहा। अतः तनकी नं. 1 विरुद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2:— आया प्रतिवादी पेरोकार सरकार विवादित भूमि राजकीय भूमि है और वादी का कोई सरोकार नहीं है? दावा न्यायोचित नहीं है?

—पेरोकार सरकार—

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब व बहस में बताया कि वादी ने अपने वाद में खातेदारी देने के पक्ष में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और वर्तमान में भी विवादित भूमि सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः तनकी नं. 1 के निर्णयानुसार: तनकी नं. 2 विरुद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः तनकीवार विवेचन करने पर यह स्पष्ट है कि वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। अतः खातेदारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

D. D.

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तादाई

जो 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.....

उनवानी दावा :

सुवालाल मुत्र श्री गोकुल जाति कीर उम्र 55 वर्ष निवासी अलेक्जेंडरपुरा तहसील देवली जिला टोंक
राज0

— वादीगण —

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार जी, देवली तहसील देवली जिला-टोंक

— प्रतिवादीगण —

दावा उद्घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 59 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामलाल कटारिया अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

खातेदारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के अभाव में वाद खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत्
खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..
..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 12 सन् 2020 को जारी किया गया।

दस्तख्त
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

मुहर

मुद्दई	रु.	पै.	मुद्दायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए